P.G. IIIrd Sem
18-20

Dr Kumari Manju
H.O.D. Eco.

Theory of Public Choice

लोक चयन का प्रारंभ इस कथन से होता है कि अर्थशास्त्र की तरह राजनीति शास्त्र में भी व्यक्ति तथा संस्थाएँ दुर्लभ साधनों के लिए स्पर्धा करती हैं। इसलिए विश्लेषण की उसी विधि जिसका प्रयोग अर्थशास्त्री उपभोक्ता तथा उत्पादनकर्ता के आचरण की व्याख्या के लिए करते हैं का प्रयोग सरकार तथा अन्य लोक संस्थाओं के आचरण की व्याख्या के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार लोक चयन राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र का आक्रमण है।

आर्थिक क्रियाओं के एक बड़े भाग का सम्बन्ध राज्य से है और ये क्रियाएँ गैर-बाजार वातावरण में होती हैं। इन गैर-बाजार क्रियाओं का अस्तित्व लोक वस्तुओं के अस्तित्व पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति कीमत का भुगतान करके निजी वस्तु प्राप्त कर सकता है, लेकिन कीमत का भुगतान करके कोई व्यक्ति लोक वस्तु के लाभ खुद अकेले ही प्राप्त नहीं कर सकता। लोक वस्तु का जब एक बार प्रावधान हो जाता है तब प्रत्येक व्यक्ति इसके लाभ को प्राप्त कर सकता है अर्थात मुफ्तखोर हो जा सकता है क्योंकि ऐसी वस्तु पर वर्जन सिद्धान्त नहीं है जैसे निजी वस्तु पर लागू होता है। ऐसी वस्तुओं के लिए लोग अपना सही अधिमान प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए प्रश्न यह उठता है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आवश्यक आवंटन किस प्रकार होगा ताकि समाज के सर्वोत्तम हित में कैसे होगा।

इस समस्या के समाधान के लिए दो विचारधाराओं का विकास हुआ है। एक विचारधारा पॉल सैम्युलसन की है जिसे उन्होंने 1954 में अपने लेख "Pure theory of Public Expenditure" में विकसित किया। उन्होंने मान लिया लिया कि एक ऐसा रेफ़री-सर्वज्ञ है जिसे लोक वस्तुओं के लिए लोगों के अधिमान की जानकारी है। इस मान्यता के आधार पर सैम्युलसन ने अपना ध्यान इस बात पर केन्द्रित किया कि निजी तथा लोक वस्तुओं के बीच किस प्रकार साधनों का कुशल आवंटन होगा है। इस विचारधारा का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ रेफ़री वास्तविकता नहीं है। अतः लोक वस्तुओं के लिए अधिमान को प्रकट करने की समस्या रह ही जाती है।

दूसरी विचारधारा विकसेल (Wicksell) द्वारा 1980 में विकसित हुआ उनके अनुसार व्यवहार में लोक वस्तुओं का आवश्यक प्रावधान किस प्रकार संभव है। मुफ्तखोरी की समस्या के कारण अधिमान को प्रकट करने की कठिनाई को देखते हुए विकसेल ने मतदान की राजनीतिक प्रक्रिया का उपयोग करके अधिमान को प्रकट करने की समस्या का समाधान सुझाया। इस प्रकार लोक चयन (Public choice) राजकोषीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गया। अमरेश बागची का कहना है कि यद्यपि लोक चयन का सिद्धान्त का प्रचलन दो शती पूर्व फ्रांसीसी गणितज्ञ ने चयन करके चयन के नियमों के गुणों को जानने का प्रयास किया था।

जोसेफ शुम्पीटर को लोक चयन सिद्धान्त का मार्गदर्शक माना जाता है किन्तु इस क्षेत्र में Landmark study ऐन्थोनी डाउन्स द्वारा हुआ। ऐन्थोनी ने इस नये सिद्धान्त को प्रतिपादित किया कि जिस तरह निजी क्षेत्र में उपभोक्ता तथा उत्पादनकर्ता लाभ को, उसी तरह उपयोगिता को अधिकतम करते हैं तथा ~~क्रियाओं को~~ नीतियों को लागू करते हैं जिनके राजनीतिज्ञ उन्हें आर्थिक ... अधिकतम होती हो उन्होंने यह भी उन्हें पुनः चुने जाने की संभावना बताया कि राजनीतिक दल राजनीतिक रंग मंच के केन्द्र में आने का प्रयास

कहते हैं। "मतदान विरोधाभास" की अवधारणा का परिचय भी उन्होंने कराया। विरोधाभास यह है कि लोगों के लिए मतदान करना विवेकपूर्ण नहीं है क्योंकि अकेला एक व्यक्ति मतदान के परिणाम को शायद ही प्रभावित कर सकता है।

बुकानन ने इस सिद्धांत को और आगे चलकर और विकसित किया। बुकानन तथा टुलॉक ने "The Calculus of Consent" नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में दोनों लेखकों ने पारम्परिक राजनीतिक सिद्धांत के भिन्न दृष्टिकोण अपनाया। पारम्परिक राजनीतिक सिद्धान्त यह मानकर चलता है कि जन प्रतिनिधि अपने संतोष या उपयोगिता को अधिकतम करने की चेष्टा नहीं करता है बल्कि सार्वजनिक हित को अधिकतम करता है। अतः जब कोई व्यक्ति निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरित होती है, तब उसका उद्देश्य निजी लाभ न होकर सामाजिक लाभ हो जाता है।

बुकानन तथा अन्य नये सार्वजनिक अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि जब लोग निजी क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो वे बदलते नहीं। व्यक्तिगत नागरिक एवं सरकारी अफसर पूर्ण निजी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें सर्वसम्मति की वकालत की। होल उनका तर्क यह है कि सर्वसम्मत निर्णय में किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं होता और अतः इस निर्णय की कोई लागत नहीं है। लेकिन ऐसा निर्णय यथास्थिति को बनाए रखता है। वस्तुतः सभी निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाते हैं।

V.K Borooah के अनुसार लोक चयन सिद्धान्त की बौद्धिक नींव निम्नलिखित पाँच अर्थशास्त्रियों द्वारा डाली गई :

Kenneth Arrow : Social choice and Individual values (1951)

A Downs : Economic Theory of Democracy (1957)

M. Olson : The Logic of Collective Action (1965)

G. Tullock : The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies and Theft.

W.D Nordhaus : The Political Business cycle (1975)

लोक चयन की प्रणाली (Mechanism of Public choice)

: प्रत्येक देश एक राजनीतिक व्यवस्था होती है जो सामूहिक निर्णय लेती है। लोक निर्णय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिमानों को सामूहिक निर्णय में बदला जाता है। प्रजातांत्रिक समाज में व्यक्तिगत रुचियों एवं मूल्यों का एकत्रीकरण करने का भी महत्व रहता है। व्यक्ति के इसी महत्व के कारण ही "एक व्यक्ति एक मत" की व्यवस्था को अपनाया जाता है। लोक चयन की प्रमुख समस्या यह है कि किस प्रकार लाखों-करोड़ों विचारों को एक, सिर्फ एक, विचार में संकलित किया जाता। उदाहरणार्थ भारत में आणविक अस्त्र बनाने के विषय में लाखों-करोड़ों विचार हैं। इन विचारों को सिर्फ एक सामूहिक विचार में परिवर्तित करना है - इसका निर्माण करना या नहीं। क्योंकि प्रजातांत्रिक देशों में लोक व्यय के स्तर का निर्धारण देश के निवासियों के व्यक्तिगत अधिमान के आधार पर होता है। सार्वजनिक वस्तु की पूर्ति विशेषतः इस कारण है कि उसका उपभोग सभी व्यक्तियों द्वारा समान मात्रा में होता है। साथ ही ऐसी वस्तुओं के व्यक्तिगत अधिमान बाजार में प्रकट नहीं होता। इसका पैरेटो के अर्थ में, कितना होना चाहिए इसका कोई एक अधिकतम उत्पादन समाधान नहीं है।

~~निजी~~ निजी वस्तुओं के मामले में बाजार निलामी पद्धति का तरह कार्य करता है तथा व्यक्ति को अपना सही अधिमान व्यक्त करने को

Scanned with CamScanner

के लिए बाध्य करता है। जब तक कोई व्यक्ति दाम नहीं बोलता तब तक वह अपनी जरूरत की वस्तु नहीं खरीद सकता। सार्वजनिक वस्तु के मामले में यह यन्त्र कारगर नहीं होता। इन वस्तुओं का वर्जन सिद्धान्त लागू नहीं होता। इनके लाभ सभी उपभोक्ताओं को मिलता है चाहे उन्होंने कीमत दी हो या नहीं। चूँकि वर्जन का सिद्धान्त लागू नहीं होता, अतः इन वस्तुओं के उपभोक्ता इनके लिए अपने सही अधिमान को स्वेच्छा से प्रकट नहीं करते। एक बात और मायने रखती है कि सामाजिक वस्तुओं के उपभोक्ताओं की संख्या सामान्यतः काफी अधिक होती है। इस कारण किसी एक व्यक्ति के द्वारा कुल लागत में कुछ भी दान नहीं बंटाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी के कारण ही उपभोक्ता ऐसी वस्तु को मुफ्त में प्राप्त करना अपने हित में मानते हैं अतः बाजार तंत्र किया नहीं कर सकता।

इस कठिनाई से बचने के लिए अर्थशास्त्रियों ने इस बात को माना कि सामाजिक वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं के अधिमान की जानकारी है। परन्तु यह व्यवहारिक नहीं है व्यवहार में राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है ताकि प्रथम व्यक्तियों के अधिमान को जाना जा सके अर्थात लोग सरकार को बता सकें कि किस सामाजिक वस्तु का प्रावधान किया जाए तथा दूसरा इसके लिए कर के रूप में कितनी प्रदान करें। यह कार्य कर तथा व्यय सम्बन्धी निर्णय पर मतदान द्वारा होता है व्यक्तियों को इतना पता है कि बहुमत से लिया गया निर्णय सभी पर लागू होगा। अतः यह उनके हित में है वे वैध ही समाधान के लिए मत दें जो उनकी इच्छा के अधिक निकट हों। इस विधि द्वारा वे अपने अधिमान को प्रकट कर सकते हैं। अधिमान की अभिव्यक्ति सही ढंग से हो इसके लिए जरूरी है कि मतदान प्रक्रिया को कर तथा व्यय दोनों के साथ जोड़ा जाए। इसका परिणाम यह होगा कि मतदाताओं के समक्ष बजट प्रस्ताव सम्बन्धी ऐसा चयन आएँगे जिनके साथ उनके स्वयं का कर योगदान कीमत के रूप में प्रकट होगा। किसी व्यक्ति को कितना कर देना होगा यह दो बातों पर निर्भर होगा। सामाजिक वस्तु की कुल लागत तथा अन्य करदाताओं का कर के रूप में योगदान। चूँकि बजट सम्बन्धी निर्णय सभी पर अनिवार्य रूप से लागू होता है, अतः लोगों को अपना निर्णय प्रकट करना ही पड़ता है। इसी से सामाजिक वस्तु की मात्रा का निर्धारण होता है।

उपर्युक्त समस्या को ही लोक चयन का सिद्धान्त (Theory of Public Choice) कहा जाता है। यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें सरकार की निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है अन्यथा हम बाजार तंत्र के दोषों को तो जान पाएँगे लेकिन राजनीतिक असफलताओं से अनभिज्ञ रह जायेंगे, हम आर्थिक व्यापार चक्र को तो जान जायेंगे लेकिन राजनीतिक व्यापार चक्र से अनजान ही रहेंगे। अतः निजी एवं सामाजिक वस्तुओं के सर्वोत्तम संयोग की प्राप्ति के लिए हमें बाजार एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के ~~आवंटन~~ के आवंटन के गुण एवं दोषों को जानना होगा। उपर्युक्त विचार मैस्ग्रेव एवं नॉरडस के हैं।

अतः राजनीतिक प्रक्रिया के विस्तार के अध्ययन की जरूरत है। यह जानने की जरूरत है कि किस प्रकार वित्तीय मामलों पर व्यक्तियों के विचार जाने जाते हैं, किस प्रकार वित्तीय निर्णय राजनीतिक निर्णय से जुड़े हैं। इसमें राजनीतिक दलों, संसद, कार्यकारिणी, निहित वर्गों, दबाव गुट आदि का क्या प्रभाव पड़ता है।

Scanned with CamScanner